यूपी पर लक्ष्मी कृपा 4 लाख करोड़ मिले

40,000

करोड़ ज्यादा मिले पिछले बजट से... 37 हजार करोड़ केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में बढ़ा

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के खजाने से उत्तर प्रदेश के लिए जमकर लक्ष्मी बरसी है। अगले वित्त वर्ष के बजट में यूपी के हिस्से में चार लाख करोड़ रुपये आएंगे। यह पिछले बजट से 40 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी पिछले बजट की तुलना में 37 हजार करोड़ रुपये बढ़ी है। केंद्र सरकार का बजट उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार में ईंधन का काम करेगा।

केंद्रीय बजट में प्रदेश की हिस्सेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पिछले वर्ष के बजट में जहां अलग-अलग मदों में प्रदेश के लिए 3.61 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था, वहीं, इस बार यह 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, कैपिटल असिस्टेंस, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हिस्सेदारी, सेंट्रल सेक्टर और वित्त आयोग के तहत मिलने वाली धनराशि शामिल है।

आगामी वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की योजनाओं में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 18 फीसदी होगी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए 84199 करोड़ रुपये का प्रावधान

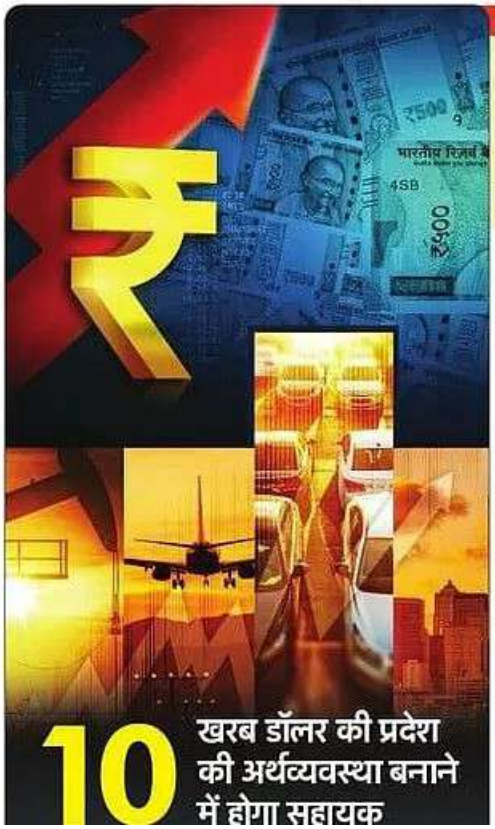

10 खरब डॉलर की प्रदेश की अर्थव्यवस्था बनाने में होगा सहायक

मद	धनराशि आवंटित (वित्त वर्ष 2024-25)	धनराशि (25-26)
केंद्रीय करों में राज्यांश	2.18 लाख करोड़ (संशोधित 2.30 लाख करोड़)	2.55 लाख करोड़
केंद्र प्रायोजित योजना	1.10 लाख करोड़	90 हजार करोड़
कैपिटल असिस्टेंस	18 हजार करोड़	18 हजार करोड़
सेंट्रल सेक्टर	13 हजार करोड़ वित्त आयोग	15 हजार करोड़
अन्य मद (लोन आदि)	15 हजार करोड़	10 हजार करोड़
कुल	3.61 लाख करोड़	4.01 लाख करोड़

6000 करोड़ से उड़ान भरेगा चमड़ा उद्योग

चमड़ा उद्योग को 6000 करोड़ का पैकेज देने का एलान किया गया। वैल्यू एडेड क्रस्ट लेदर और वेट ब्लू लेदर से कस्टम ड्यूटी भी खत्म की गई है। इससे अगले पांच साल में यूपी की लेदर इंडस्ट्री 25 लाख नए रोजगार और 20 हजार करोड़ का नया कारोबार खड़ा करेगी।

ये भी खास

तीन करोड़ किसानों को फायदा

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिये किसानों को अब तीन के बजाय पांच लाख रुपये तक के ऋण पर छूट मिलेगी। इससे प्रदेश के तीन करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।

एमएसएमई में 10 लाख युवाओं को रोजगार

देश की 5.7 करोड़ एमएसएमई का ख्याल रखा गया है। इस सेक्टर के लिए की गई घोषणाओं से यूपी की एक करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाइयां भी लाभान्वित होंगी। 2000 से ज्यादा नई इकाइयां पैदा होंगी और 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।